

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

विविध :: 48/2022

जीसीएमएस नम्बर :: 2022/143

प्रार्थी :-

बनाम

अप्रार्थीगण :-

आदर्श कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय- आदर्श भवन तीन बती, पोस्ट बॉक्स नं. 32, सिरौही- 307001 (राजस्थान) अन्य शाखा :- आदर्श कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मण्डिया रोड, ऑपोजिट-एलआईसी बिल्डिंग, पाली- 306401 (राजस्थान) जरिये प्रतिनिधी शैतान सिंह पुत्र ओट सिंह जी ईन्दा, प्राधिकृत अधिकारी आदर्श कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

1. मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) अन्य पता :- 138, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड, पाली- 306401 (राजस्थान)
2. श्री दीप सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 138, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड, पाली-306401 (राज.)
3. श्री खुशाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह 81, दुर्गा कॉलोनी, रामदेव रोड, पाली-306401 (राजस्थान)
4. श्री ओमप्रकाश भारद्वाज पुत्र श्री भंवरलाल भारद्वाज 161, महात्मा गाँधी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान)
5. श्री पंकज कुमार छौगानी पुत्र श्री केवलचन्द छौगानी 167, सिन्धी कॉलोनी, पाली 306401(राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटि इन्टरस्ट, 2002

दिनांक:- 05.05.2022

1. यत प्राधिकृत अधिकारी, आदर्श कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम -2002 SARFAESI Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना-पत्र जरिये प्रतिनिधि शैतान सिंह पुत्र ओट सिंह जी ईन्दा ने मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।
2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता/प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी/ऋणी को बैंक/कंपनी द्वारा दिनांक 29.09.2020 को 90,00,000 /- (नब्बे लाख रुपये) का ऋण स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद/सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. First property situated at part of Plot No. 121, Nadi Mohalla, Pali (Rajasthan) admeasuring about 2400 Sq. Feet which have in East is 30 Feet wide road, in West is Remainingpart of patta suda plot, in North is Remaining part of patta suda plot and in South is Remianing part of patta suda plot
2. Second property situated Khasra No. 901/1, Durga Colony, Ramdev Road, Pali - 306401 admeasuring about 500 Sq. Feet, Which have in East Other House, in West 20 Feet Wide Road, in North House of Tolaram Brahmin and in South House of Shyamlal Vaishnav
3. Third property situated at Plot No. 327, Marwar City, Manpura, Pali - 306401 (Rajasthan) admeasuring about 125.56 sq. Yards, Khasra No. 42 and 44 Which have in East is Plot No. 332, in West is 22 Feet Wide road, in North is Plot No. 328 and in South is Land of Khasra No. 44
4. Forth property is situated at Plot No. 332, Marwar City, Manpura, Pali - 306401 (Rajasthan) admeasuring about 123 Sq. Yards, Khasra No. 42 and 44 Which have in East is 25 feet Wide road, in West is Plot No 327, in North is plot No. 333 and in south is land of khasara No. 44



जिला मजिस्ट्रेट, पाली

2 | विविध : 48/2022 "आदर्श कॉ. बैंक लि. बनाम मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी एवम् अन्य "

3. चूंकि ऋणी फलस्वरूप अप्रार्थी मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) के द्वारा बैंक/कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 30.11.2021 को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।
4. फलस्वरूप अप्रार्थी मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) ऋणी एवं इसके समस्त जमानतियों के द्वारा SARFAESI Act की के तहत ऋण राशि मय ब्याज 91,00,600.90/- (इक्याानवे लाख छः सौ रुपये नब्बे पैसे) दिनांक 30.11.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए भुगतान हेतु बकाया है। SARFAESI Act की धारा 13(2) के तहत बकाया भुगतान करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 16.12.2021 को भेजा गया इसके बाद भी अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया।
5. फलस्वरूप अप्रार्थी मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) को ऋणी द्वारा देय ऋण राशि का 60 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त भी भुगतान नहीं किये जाने से प्रार्थी कम्पनी द्वारा व्यथित होकर सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत इस न्यायालय में ऋणी द्वारा ऋण पेटे गिरवी रखी गयी सम्पत्ति जो कि प्रार्थना पत्र में वर्णित है, का कब्जा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया।
6. प्रार्थी कम्पनी/बैंक के इस प्रार्थना-पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थी पक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।
7. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता/बार द्वारा कार्य स्थगन के कारण 60 दिवस की उक्त अवधि में प्रकरण का निस्तारण किया जाना संभव नहीं हो सका।
8. हमने प्रार्थी के द्वारा सरफेसी की धारा 14 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी ने ऋण का भुगतान कर दिया गया हो। सरफेसी एक्ट के तहत इस न्यायालय को मात्र पुलिस ईमदाद देने की हद तक सीमित अधिकार है। प्रार्थना पत्र एवं इसके लगाये दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कंपनी के द्वारा फलस्वरूप मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) एवं उसके जमानतियों को ऋण वसूली हेतु इस अधिनियम की धारा 13(2) में नोटिस दिया गया है, जिसका संवहन (Deliver) ऋणी को हो जाना स्पष्टतया पाया जाता है। तदुपरान्त भी निर्धारित 60 दिवसीय अवधि समाप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के नही चुकायी गयी है, जबकि दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेसियर्स एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रेस्ट अधिनियम -2002 की धारा 14 में रहन (Mortgage) रखी गयी सम्पत्ति को कब्जे में ली जाकर प्रार्थी को दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार है :-

Section 14 Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1) where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provision of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate withing whoes jurisdiction any such secured asset or other documents relating theirto may be situlated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him -

- (a) take possession of such asset and documents relating thereto; and
- (b) forward such asset and documents to the secured creditor

Provided that any application by the secured creditor shall be accompanied by an affidavit duly affirmed by the authorised officer of the secured Creditor, declaring that:

जिला सजिस्ट्रेट, पाली

3 | विविध : 48/2022 "आदर्श कॉ. बैंक लि. बनाम मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी एवम् अन्य "

- (i) the aggregate amount of financial assistance granted and the total claim of the bank as on the date of filing the application.
- (ii) The borrower has created security interest over various properties and that the Bank or Financial Institution is holding a valid and subsisting security interest over such properties and the claim of the Bank or the Financial is within the limitation period.
- (iii) The borrower has created security interest over various properties giving the details of properties referred to in the sub clause (ii) above :
- (iv) The borrower has committed default in repayment of the financial assistance granted aggregating the specified amount:
- (v) Consequent upon such default in repayment of the financial assistance the account of the borrower has been classified as non performing asset:
- (vi) Affirming that the period of sixty days notice as required by the provisions of sub section (2) of section 13, demanding payment of the defaulted financial assistance has been served on the borrower:
- (vii) The objection and representation in reply to the
- (viii) notice received from the borrower has been considered by the secured creditor and the reasons for non-acceptance of such objection or representation had been communicated to the borrower:
- (ix) The borrower has not made any repayment of the financial assistance in spite of the above notice and the Authorised Officer is, therefore, entitled to take possession of the secured asset under the provision of sub section (4) of section 13 read with section 14 of the principal Act:
- (x) That provisions of this Act and the rules made there under had been complied with"

" Provided further that on receipt of the affidavit from Authorised Officer, The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall, after satisfying the contents of the affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured asset ¹[within a period of thirty days from the date of application]:

¹[Provided further that if no order passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thirty days for reason beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty day]

Provided also that the requirement of filing affidavit stated in the first proviso shall not apply to proceeding pending before any District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, on the date of commencement of this Act)

²(1A) The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate may authorise any officer subordinate to him --

- (i) to take possession of such asset and documents relating thereto; and
- (ii) to forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be

taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

(3) No act of the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate ¹[any officer authorised by the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate]



done in pursuance of this section shall be called in question in any court or before authority.

9. अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के मध्येनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 में प्रार्थी बैंक/कंपनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि अप्रार्थी मैसर्स मातेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री दिनेश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खुशाल सिंह 47, सिन्धी कॉलोनी, पाली-306401 (राजस्थान) इस आदेश से पन्द्रह दिन की अवधि में ऋण का भुगतान नहीं करता है तो पैरा संख्या 2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पत्ति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली को निर्देश प्रदत्त किये जाते हैं तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके एवं यदि संपत्ति में कोई किरायेदार है तो उस संपत्ति को छोड़ने हेतु समुचित समय देने के उपरांत ही पैरा 2 में वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द करेंगे। यदि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा बकाया ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो इस आदेश की कार्यवाही नहीं की जावे। जिला पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली को आवश्यकतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैंक /कंपनी अप्रार्थीगण को देवे।

10. आदेश आज दिनांक 05.05.2022 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(नमित मेहता)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली